

14.41 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) *Early completion of Irrigation Projects in vidisha (Madhya Pradesh).*

श्री प्रतापभानु शर्मा (विदिशा) : विदिशा, रायसेन संसदीय क्षेत्र की कई लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाएँ पिछले दो द्वाइ वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वन विभाग को डूब में आने वाली भूमि की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। कई स्वीकृत सिंचाई योजनाओं का कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं किया जा सका है कि उनमें केवल 20-25 हैक्टर वन भूमि डूब में आ रही है और इन सिंचाई परियोजनाओं को आज दिनांक तक वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके कारण हजारों लघु एवं सीमान्त कृषक इन सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए हैं तथा राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का नुकसान भी हो रहा है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि—

1. जिन विकासखंडों में सिंचाई 7 प्रतिशत से कम है वहाँ की सर्वेक्षित एवं स्वीकृत सभी सिंचाई योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए।

2. और जिन योजनाओं का कार्य केन्द्रीय सरकार एवं वन विभाग की अनुमति के लिए रुका है उन सभी प्रकरणों का निपटारा केन्द्र और राज्य शासन के वन तथा सिंचाई विभाग अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा तुरन्त स्थल निरीक्षण कर स्वीकृति प्रदान कर किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि उक्त कार्यवाही करने से इन योजनाओं के निर्माण कार्य में गति आएगी।

(ii) *Demand for Financial Assistance to the desert region equal to that of hilly areas.*

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : केन्द्र सरकार ने देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए जो अभिरुचि दिखानी चाहिए नहीं दिखाई जिसके फलस्वरूप ये देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में हैं।

योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र के लिए योजना में अलग से अध्याय कायम कर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 175 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 560 करोड़ रुपया कर दिया। केन्द्र से विशेष सहायता के अंतर्गत उक्त राशि निर्धारित कर केन्द्र से 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर सन् 1977-78 में मरू-विकास कार्यक्रम चालू किया जो केन्द्रीय संचालित योजना की तरह चला। केन्द्र सरकार सारी राशि अनुदान में देती थी परन्तु 1.4.79 से उक्त योजना को परिवर्तित कर आधी राशि केन्द्र सरकार से और आधी राशि राज्यों की ओर से देने का निर्णय लिया जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों पर बड़ा कुठाराघात हुआ।

केन्द्र सरकार ने उक्त मरू क्षेत्र के जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से पहाड़ी क्षेत्र से बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर आधा है। केन्द्र सरकार ने बहुत कम राशि 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो उक्त क्षेत्र की जनता के प्रति घोर उपेक्षा का सूचक है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, संचार, विद्युत, वन एवं कृषि विकास की दृष्टि से रेगिस्तानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, यू० पी० आदि से बहुत ही पीछे है।

अतः निवेदन है कि केन्द्र सरकार और योजना आयोग पुनर्विचारकर रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के समान सुविधा उपलब्ध करावे और छठी पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपये और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान करें और उक्त क्षेत्र में केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण का प्रबंध करें।

(iii) *Need for establishment of ancillary Industries alongwith Railway Carriage Repair Workshop at Tirupathi (Andhra Pradesh).*

SHRI PASALA PENCHALIAH (Tirupathi) : The Central Government sanctioned a Railway carriage repair workshop at the cost of Rs. 12 crore at Tirupathi. I am happy to say that the preliminary work is going in with good progress. Recently, the South Central Railway displayed 242 items of ancillaries and accessories at Tirupathi required for functioning of the workshop and appealed to the local entrepreneurs to make use of the opportunity to manufacture these products through small scale industries. But the Railway authorities have not assured that they would purchase these parts from Local Small Scale Industries. In these circumstances, it is doubtful whether local small scale industries could sustain the competition from bigger and established industries in the absence of assured market for their products.

To encourage local entrepreneurs and small scale industries, the Railway authorities should buy the local manufactured products after prescribing their own standards of specifications as is being done by other major public sector undertakings like B.H.E.L., E.C.I.L., H.M.T. etc., taking into consideration the backwardness of the Rayalaseema area in Andhra Pradesh.

Alternatively the South Central Railway should start the ancillary industries as is being done in other Railway factories. This would provide at least employment to about 2000 people of that area.

Therefore, I urge upon the Railway Minister to take necessary steps to consider either to set up ancillary industries by Railways or encourage local small scale industries by giving them ancillary status as otherwise the purpose of establishing of Railway carriage repair workshop to develop backward area would be defeated.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, under your residuary power, would you allow an hon. Member to make an ex-tempore statement under Rule 377 ?

MR. DEPUTY SPEAKER : No reply to your question.

(iv) *Need for punctuality of and security in Trains.*

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : The punctuality of train services in the Railways in the recent months has deteriorated to an extent that one does not know when he is to reach the destination once he boards the train. This statement of mine bears the testimony at least on three occasions when I had travelled by Neelachal Express. But it is the general complaint by the passengers who avail of these pairs of train services from Puri to New Delhi that instead of punctuality being maintained, the train is always punctual, being late, in the reverse direction.

Not only the trains run late every time but amenities and security provided have been reduced as well. On the 31st May, 1983, I was surprised to know that no conductor remained on duty from Mughalsarai to Gomo Railway Stations at night. As a result, I found on that particular day that genuine passengers were evicted in ACC 2 Tier Coach and all kinds of unauthorised persons occupied the reserved berths. In spite of our best efforts, we could not help getting the berths in their favour or could find out the conductor on duty. In the recent months, there have been dacoities in this train thrice and no one helps the victims, although security is being assured here in the House every now and then for the travelling passengers.